

ISSN: 2249-2577

वर्ष 11 अंक 1
जनवरी-जून, 2019

लोक प्रशासन

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली
की अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

संपादक
प्रो. एस. एन. मिश्र

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

अध्यक्ष

निदेशक, आई. आई. पी. ए.,
नई दिल्ली

सम्पादक

प्रो. एस. एन. मिश्र
नोएडा

सम्पादक मंडल

प्रो. के. के. पाण्डेय
आई. आई. पी. ए., नई दिल्ली

प्रो. अमिता सिंह
जे.एन.यू., नई दिल्ली

प्रो. श्रीप्रकाश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डा. प्रवीण कुमार
प्राचार्य, श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली

डा. अशोक कुमार पाण्डेय
भूतपूर्व आई.ए.एस., नई दिल्ली

पाठ-संशोधक

स्नेहलता

वार्षिक शुल्क : आजीवन सदस्य-रु. 150, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 200, संस्थागत ग्राहक-रु. 300
सामान्य अंक : आजीवन सदस्य-रु. 75, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 100, संस्थागत ग्राहक-रु. 150
विशेषांक : आजीवन सदस्य-रु. 100, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 200, संस्थागत ग्राहक-रु. 200

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002

Yksd i z kkl u

vu0ef.kdk

i "B

I Ei kndh;

v

Yksk

लोकनीति पर सामाजिक आन्दोलनों का प्रभाव श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी	1
भारत में राष्ट्रीय एकीकरण: सांस्कृतिक विरासत, समस्याएँ एवं समाधान शशि भूषण कुमार	8
ग्राम सभा : भारतीय लोकतंत्र का प्रथम सोपान गाँधीजी राय एवं शेखर कुमार	24
भारत में लोक नीतियों का क्रियान्वयन सुरेन्द्र कुमार	41
आधुनिक भारत में शहरी सुशासन: 74वाँ संविधान संशोधन के परिपेक्ष्य में उमेश कुमार	48
लोकनीति और उनके प्रतिमान सुमन कुमार शर्मा	58
मध्यप्रदेश में आदिवासी महिलाओं का अध्ययन और उदारीकरण का प्रभाव दुर्गेश तेली	66
लोकनीति एवं नीति निर्मात्री संस्थाएँ अम्बुजेश कुमार मिश्र	82
सुशासन और लोकनीति महेश कुमार सिंह	89
विकासशील देशों में विकास प्रशासन की भूमिका स्निग्धा त्रिपाठी	97

प्रवासी भारतीय एवं भारत सरकार— संक्षिप्त अध्ययन शीला कुमारी	104
ग्रामीण विकास की योजनाओं में भारत सरकार का योगदान : एक मूल्यांकन मो. ताहिर अन्सारी	123
औपनिवेशिक प्रशासन तथा बाढ़ नियंत्रण : उत्तर बिहार का विशेष सन्दर्भ निशा कुमारी	129
बांग्लादेश में इस्लामिक उग्रवाद का बदलता स्वरूप और उसकी चुनौतियाँ रवीन्द्र कुमार मीना	139
भारत में निर्धनता की समस्या : चुनौतियाँ और समाधान राजबीर सिंह दलाल एवं जगजीत सिंह	147

yskd

प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी – आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।

डॉ. शशि भूषण कुमार – सह-आचार्य, स्नातकोत्तर, राजनीति शास्त्र विभाग, आर. एन. महाविद्यालय, हाजीपुर, बिहार ।

प्रो. गाँधीजी राय – सेवा निवृत्त, आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार ।

डा. शेखर कुमार – प्राध्यापक, सह-प्रशासक महाराजा लॉ कॉलेज, आरा, बिहार ।

डॉ. उमेश कुमार – आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, लोक प्रशासन विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार ।

डॉ. सुरेन्द्र कुमार – अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, बी. एस. कॉलेज, दानापुर, पटना, बिहार ।

डॉ. सुमन कुमार शर्मा – सह-आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग, राजकीय आर्ट्स, पी.जी. कॉलेज, सीकर, राजस्थान ।

डॉ. दुर्गेश तेली – शोध छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

श्री अम्बुजेश कुमार मिश्र – शोध छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।

शीला कुमारी – शोध छात्रा, राजनीति शास्त्र विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार ।

स्निग्धा त्रिपाठी – शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।

श्री महेश कुमार सिंह – शोध छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।

मो. ताहिर अन्सारी – शोध छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।

निशा कुमारी – शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

प्रो. राजबीर सिंह दलाल – आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा ।

श्री जगजीत सिंह – शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा ।

श्री रविन्द्र कुमार मीना – शोध छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली ।

I Eikndh;

कौटिल्य ने नीति के महत्त्व को बताते हुए कहा है कि आत्मगुण सम्पन्न राजा छोटे देश का स्वामी होते हुए भी प्रभुत्व-सत्ता की प्रकृतियों से युक्त होकर अपनी 'नीति' के बल से सारी पृथ्वी को जीत सकता है और कभी पराजित नहीं होता।

'नीति' का अध्ययन जिस विषय के रूप में किया जाता है उसे नीति विज्ञान (Policy Science) कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के चिन्तक एवं नीति विज्ञान को आगे लाने में हैराल्ड लॉसवेल (Harold D. Lasswell) का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लॉसवेल ने सर्वप्रथम 1951 में अपने प्रकाशित लेख 'The Policy Orientation' (नीति अभिविन्यास) में 'Policy Science' (नीति विज्ञान) शब्दों का प्रयोग कर नीति विज्ञान की अवधारणा का प्रतिपादन किया।

लोकनीति का निर्माण शून्य में नहीं होता है। नीति का निर्माण सरकार अथवा शासन की सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है। इसे लोक प्रशासन एवं राजनीति का केन्द्रीय तत्व माना जाता है क्योंकि नीति निर्माण प्रक्रिया में सरकार के तीनों अंग— विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एक-दूसरे से सम्बद्ध होते हैं। लोक नीतियाँ किन्हीं मुद्दों अथवा एजेण्डा पर आधारित होती हैं। चूँकि भारत एक लोककल्याणकारी राज्य है तथा संसदीय व्यवस्था की शासन प्रणाली को अपनाते हुए लोकतंत्र का प्रहरी है जिसमें अधिकतम लोगों के कल्याण की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए किन्हीं समस्याओं, मुद्दों, कार्यक्रमों, योजनाओं पर नीति बनाई जाती है।

नीति निर्माण के दो मार्ग हैं— एक तो जनता के द्वारा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जो विधानमण्डल तथा मंत्रिमंडल में होते हैं और दूसरा प्रशासनिक तन्त्र द्वारा उनके अपने ही उत्तम माध्यम से। इन दोनों मार्गों का मिलन स्थल मंत्रिमंडल होता है। सभी देशों में नीति निर्माण की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। नीति के निर्माण में संवैधानिक घटकों के साथ-साथ गैर-संवैधानिक घटक भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। लोक नीति का क्षेत्र व्यापक है और नीतियाँ शासन के तीनों स्तरों पर अपने-अपने विषय क्षेत्र में निर्मित होती हैं। ये तीन स्तर हैं— संघीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। संघ और राज्यों के कार्यों में सन्तुलन एवं समन्वय बनाये रखने के लिए तीन सूची हैं— संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिससे नीति निर्माण में स्पष्टता एवं एक सीमा बनी रहे।

लोक नीति मात्र सरकार का तकनीकी कार्य ही नहीं है वरन् यह एक जटिल - प्रक्रियात्मक प्रक्रिया है, जो विभिन्न प्रकार की पारिस्थिकीय प्रवृत्तियों के द्वारा प्रभावित होती है, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि के द्वारा। ये पारिस्थिकीय कारक तत्व 'नीति संदर्भ' निर्धारित करते हैं तथा हर

नीति को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित एवं निर्मित करते हैं, साथ ही साथ उसके प्रभावों को भी नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि विकसित देशों की नीतियाँ विकासशील देशों से भिन्न हैं। ऐसी नीतियाँ जो एक प्रशासनिक व्यवस्था में सफल हैं, वे आवश्यक नहीं हैं कि अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी सफल होंगी क्योंकि हर प्रशासनिक व्यवस्था की अपनी परिधि है, जो उसकी विशेषताओं को सीमित करती है।

सरलतम शब्दों में लोकनीति निर्माण में नीति एक वृहद् कथन है जो भविष्य के उद्देश्यों, अपेक्षाओं को प्रतिबिम्बित करता है तथा मार्गदर्शन करता है कि इन उद्देश्यों तक कैसे पहुँचा जा सकता है।

श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी ने अपने लेख में भारत में लोक नीतियाँ किस प्रकार से सामाजिक आन्दोलनों से प्रभावित होती रहती हैं, तथा सामाजिक आन्दोलन सदैव प्रशासन पर नई नीतियों को क्रियान्वित करने के लिये दबाव डालते रहते हैं, इसका उल्लेख किया है। इस शोध पत्र में किसान आन्दोलन, कामगार आन्दोलन, नारी आन्दोलन, दलित और जनजातीय आन्दोलनों के लोक नीतियों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी विशेष रूप से विवेचन किया गया है।

21वीं सदी के भारत के सम्मुख अनेक गंभीर समस्याओं में से एक राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या है। राष्ट्रीय एकीकरण एक बहु आयामी अवधारणा है। इसके राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक इत्यादि अनेक पक्ष हो सकते हैं, फिर भी मूल रूप में यह ऐसी सामुदायिक या राष्ट्रीयता की भावना है जो विविध समुदायों को एकता के सूत्र में बांधती है ताकि सांस्कृतिक, जातियों भाषाओं व धर्मों के अन्तर को भावनात्मक दृष्टि से सम्पूर्ण इकाई के रूप में ग्रहण किया जा सकें। इसका विश्लेषण शशि भूषण कुमार ने अपने लेख में बखूबी किया है।

ग्राम सभा भारतीय लोकतंत्र का प्रथम सोपान है। इसका विश्लेषण गांधीजी राय व शेखर कुमार ने अपने लेख में किया है कि कैसे ग्राम सभा के मार्ग को विभिन्न समस्याएं अवरुद्ध कर रहीं हैं परन्तु इसके बावजूद ग्रामीण विकास प्रक्रिया में ग्रामीण जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभर रही है।

सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियों व कार्यक्रमों का निर्माण करती है। जब नीति सरकार बनाती हैं तो उसे लोकनीति कहते हैं। सरकार सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करती है। किसी भी नीति की सफलता या विफलता इसके क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है। अतः विकासशील देशों के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण नीतियाँ एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना है। यह सुरेन्द्र कुमार ने अपने लेख में प्रस्तुत किया है।

आधुनिक भारत में शहरी सुशासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लिए सरकारी तंत्र की व्यवस्था है। स्थानीय प्रशासन कस्बे, नगर और महानगर की प्रगति के लिए

एक महत्वपूर्ण संस्था है। उमेश कुमार ने अपने लेख में 74वें संविधान संशोधन के परिपेक्ष्य से शहरी सुशासन की व्याख्या की है कि किस प्रकार युवा पीढ़ी भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्षरत हो जाये। इससे स्वप्रशासन अध्यक्ष देश का सही ढंग से जनता के हित में कार्य कर सकेगा।

सुमन कुमार शर्मा के लेख का मुख्य उद्देश्य लोकनीति और इसके प्रतिमान का सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत करना है। लोकनीति एक अनुसंधान के रूप में बीसवीं शताब्दी के मध्य दशक के प्रारम्भ में उद्भवित हुई और वर्तमान दैनिक जीवन और शैक्षणिक परिवेश में लोकनीति एक प्रचलित धारणा बन गयी है।

अपने लेख में दुर्गेश तेली ने मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं का अध्ययन और उन पर उदारीकरण के प्रभाव के बारे में लिखा है। आदिवासी जनजातीय समुदाय मुख्यतः जंगलों, पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। इनका व्यवसाय व आजीविका यहीं से संसाधनों के द्वारा चलती है। हम उदारीकरण के संदर्भ में आदिवासी समुदायों की महिलाओं की स्थिति के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे।

जनता की विभिन्न माँगों और समस्याओं के समाधान के लिये सरकार जो नीतियाँ बनाती हैं उन्हें लोकनीति कहा जाता है। यह सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधि है, क्योंकि यह नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती है। लोकनीति के निर्माण के लिये विभिन्न संस्थायें सहयोगी की भूमिका निभाती हैं। जिनके अभाव से इन नीतियों का निर्धारण नहीं हो सकता। इसका विवेचन अम्बुजेश कुमार मिश्र ने प्रस्तुत किया है।

सुशासन और लोकनीति वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विकास के निर्णायक एवं अनिवार्य घटक के रूप में विद्यमान है। सुशासन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध किसी की शासन प्रणाली के स्वरूप से न होकर जनता को उपलब्ध कराये जाने वाली गुणवत्तायुक्त संसाधनों से है इसलिये सरकार द्वारा ऐसी नीतियाँ बनाई जायें जो सुशासन के लिए जरूरी हो क्योंकि इन्हीं नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन से हम सुशासन को उपलब्ध करेंगे। यह महेश कुमार सिंह ने अपने लेख में बताने का प्रयास किया है।

विकास प्रशासन लोक प्रशासन की नूतन विद्या है। यह एक प्रगतिशील व परिवर्तनशील अवधारणा है। वर्तमान समय में विकासशील देशों में विकास प्रशासन मात्र नीति कार्यान्वयन तक सीमित न रहकर जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्रमिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जिससे मानव व समाज का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। इसका स्निग्धा त्रिपाठी ने अपने लेख में विवेचन किया है।

प्रवासी भारतीयों में भारतीय मूल के लोग और प्रवासी भारतीय शामिल हैं। जिन्हें भारत और इसके आंतरिक मूल्यों का विचार एक आम सूत्र में बांधे हुए है।

प्रवासी भारतीयों ने अपने आवास के देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के पास वर्तमान में 25 मिलियन का एक सशक्त प्रवासी भारतीय समुदाय है। यही कारण है कि प्रवासी आबादी के महत्व को देखते हुए इनके साथ भारत सरकार द्वारा एक संस्थागत ढाँचा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी का विश्लेषण *शीला कुमारी* ने अपने लेख में किया है।

मो० ताहिर अन्सारी के लेख में ग्रामीण विकास की योजनाओं में भारत सरकार के योगदान तथा मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल इंडिया आदि योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की समकालीन योजनाओं को विस्तृत ढंग से समझा जा सकता है।

औपनिवेशिक प्रशासन की यह मान्यता थी कि नदियों के बहाव को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जिसके फलस्वरूप नदियों पर व्यापक रूप से तटबंधों तथा अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया। औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा यह प्रयास अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया जिसका स्थानीय जन-जीवन पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। *निशा कुमारी* का लेख भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण के विभिन्न प्रयासों के वर्णन के माध्यम से पर्यावरण के औपनिवेशीकरण तथा विशेष रूप से नदियों के औपनिवेशीकरण का विश्लेषण करने का एक प्रयास है।

वर्तमान समय में बांग्लादेश इस्लामिक उग्रवाद के एक नए केन्द्र के रूप में उभरा है जिसका ज्वलंत उदाहरण ढाका में 1 जुलाई 2016 के आर्टिशन कैफे पर हुए हमले के रूप में देखा जा सकता है। देश में समकालीन इस्लामिक उग्रवाद के इस स्वरूप को उभारने में वस्तुतः कई कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक घरेलू राजनीतिक दशा, विशेष इस्लामिक संस्कृति की उपज तथा वैश्विक परिदृश्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह *रविन्द्र कुमार मीना* ने अपने लेख में प्रस्तुत किया है।

भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक गरीबी है। यह एक आर्थिक और सामाजिक दोनों समस्या है। वर्तमान समय में गरीबों को आंकना भी एक नई चुनौती है। क्योंकि लोक नियंत्रण आधारित संसाधन लगातार कम हो रहे हैं। गरीबी को मिटाना संभव है परन्तु इच्छाशक्ति नहीं है। अवसरों और विकल्पों का अभाव ही गरीबी है। इसका विवेचन *राजबीर सिंह दलाल* एवं *जगजीत सिंह* ने अपने लेख में प्रस्तुत किया है।

लोकनीति पर सामाजिक आन्दोलनों का प्रभाव

श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी

लोक नीतियाँ सामाजिक आन्दोलनों से प्रभावित होती रहती हैं। सामाजिक आन्दोलन सदैव प्रशासन पर नई नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए दबाव डालते रहते हैं। सामाजिक आन्दोलन किसी भी देश में सामाजिक परिवर्तन और सरकार की नीतियों को परिवर्तित करने का सशक्त माध्यम है। प्रस्तुत शोध-पत्र, में भारत में लोक नीतियाँ किस प्रकार से सामाजिक आन्दोलनों से प्रभावित होती हैं, इसका उल्लेख किया गया है। इस शोध पत्र में किसान आन्दोलन, कामगार आन्दोलन, नारी आन्दोलन, दलित और जनजातीय आन्दोलनों के लोक नीतियों पर पड़ने वाले प्रभावों का विशेष रूप से विवेचन किया गया है।

भारत में राष्ट्रीय एकीकरण: सांस्कृतिक विरासत, समस्याएँ एवं समाधान

शशि भूषण कुमार

I kjkk: 21वीं सदी के भारत के सम्मुख अनेक गंभीर समस्याओं में से एक राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या है। आजादी के 71 वर्षों के उपरांत आज भी भारत में सामाजिक - आर्थिक - राजनीतिक उथल - पुथल, आंतकवादी घटनाओं, विभाजनकारी आंदोलनों तथा सांप्रदायिक एवं जातीय झगड़े दृष्टिगोचर हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही तृतीय विश्व के राष्ट्रों को, जिसमें भारत भी एक है, उन सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से जूझना पड़ा जो पश्चिमी राष्ट्रों के सम्मुख क्रमशः आई थीं। राजनीतिक क्रांति के साथ ही उन्हें एक अन्य अधिक मूलभूत क्रांति से भी गुजरना पड़ा है जिसका उद्देश्य सामाजिक विविधता में से राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना है। इस प्रकार तृतीय विश्व के राष्ट्रों को एक साथ परिवर्तन व एकीकरण की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है।¹ रजनी कोठारी के अनुसार "राजनीतिक विकास की बुनियादी समस्या एकीकरण की है अर्थात् नए राजनीतिक केन्द्र - बिन्दु की स्थापना और सुदृढीकरण, उनका बहुमुखी विस्तार, विभिन्न संस्थाओं का पल्लवन, विविधता को एक सूत्र में संग्रहण कर एक राष्ट्र का निर्माण अर्थात् एकीकरण की क्षमता का विकास; यही समस्या हमारे राष्ट्र-निर्माताओं के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या रही है"²। भारत जैसे विविधतायुक्त राष्ट्रों के लिए यह एक कठिन प्रक्रिया है क्योंकि यह अभी भी संक्रमण की अवस्था में है जहाँ आधुनिकीकरण के प्रयास में ये एकीकरण के परम्परागत तत्वों को तो छोड़ चुके हैं लेकिन ऐसी नवीन परम्पराओं की स्थापना नहीं कर पाए जो राष्ट्रीय एकीकरण का माध्यम बन पातीं।

ग्राम सभा : भारतीय लोकतंत्र का प्रथम सोपान

गाँधीजी राय एवं शेखर कुमार

l kjkl% ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की प्रथम व्यवस्थापिका सभा है। यह उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। व्यवहार के आधार पर यह **ipk; rh jkt** का लोक केंद्रित स्वरूप है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गाँव की जनता द्वारा निर्वाचित सभी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ग्राम सभा में उपस्थित होकर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणा को सुदृढ़ करते हैं। यह भारतीय गणतंत्र का सबसे अनूठा और पंचायती राज का सबसे मौलिक स्वरूप है। "जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार"¹ की लोकतंत्र की अवधारणा को भारत में सही अर्थ में ग्राम सभा ही चरितार्थ करती है और इसीलिए यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जीता-जागता स्वरूप है। इसके कार्यों के निष्ठापूर्वक निष्पादन से देशांतर्गत 'चमकते भारत' (shining India) की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। यही कारण है कि विविध सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा ग्राम सभा को शक्ति संपन्न और सक्रिय बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

भारत में लोक नीतियों का क्रियान्वयन

सुरेन्द्र कुमार

किसी भी नीति की सफलता या विफलता इसके क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है। कोई भी नीति कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, यदि उसका क्रियान्वयन प्रभावशाली नहीं है तो ऐसी नीति का कोई महत्त्व नहीं। अगर नीति विफल होती है तो सरकार विफल होती है। विकसित देशों की तुलना में भारत जैसे विकासशील देशों में नीतियों का क्रियान्वयन एक बड़ी समस्या है। इन देशों में कागज पर आकर्षक नीतियाँ तो बनाई जाती हैं, किन्तु इनका क्रियान्वयन प्रभावी नहीं हो पाता। अतः, विकासशील देशों के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना है।

आधुनिक भारत में शहरी सुशासन: 74वाँ संविधान संशोधन के परिपेक्ष्य में

उमेश कुमार

। kjkdk% शहरी शासन का शाब्दिक अर्थ शहरी क्षेत्र के लिए सरकारी तंत्र की व्यवस्था है। शासन किसी निकाय, संगठन अथवा संस्था को संचालित करने की प्रक्रिया अथवा शक्ति है। शहरी शासन की अवधारणा इस तथ्य में निहित है कि शहरी क्षेत्र को किस प्रकार की शासकीय इकाई द्वारा शामिल किया जा रहा है जिसका गठन शहरी क्षेत्र के विकास हेतु किया गया है। शहरी शासन की अवधारणा अत्यंत जटिल है। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है बल्कि विभिन्न प्रक्रियाओं, संस्थाओं एवं व्यक्तियों की एक सामूहिक संस्था है, जहाँ लोग एक श्रृंखला में एक-दूसरे के समन्वय के साथ कार्य करते हैं और अपने पर्यवेक्षकों के प्रति समान रूप से जवाबदेह होते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति व स्थान को ध्यान में रखा जाता है जहाँ विधिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है, दायित्वों का निर्वहन किया जा सकता है और मतभेदों को दूर किया जा सकता है।

लोकनीति और उनके प्रतिमान

सुमन कुमार शर्मा

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य 'लोकनीति और उसके प्रतिमान' का सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत करना है। लोकनीति एक अनुसंधान के रूप में बीसवीं शताब्दी के मध्य दशक के प्रारम्भ में तब उद्भवित हुई, जब इसके प्रतिमान में एक नूतन कलेवर का संचार हो रहा था। वर्तमान परिदृश्य में यह एक नूतन विद्या की परिस्थिति प्राप्त करने का प्रबल प्रयास कर रहा है। लोकनीति के निरन्तर प्रगति से इसमें जटिलता एवं कलिष्टता का पुट परिलक्षित हो रहा है, जो अनुसंधानकर्त्ताओं, शिक्षकों एवं प्रशासकों के अन्वेषण का रोचक एवं विचारोत्तेजक विषय बनता जा रहा है। वर्तमान दैनिक जीवन और शैक्षणिक परिवेश में 'लोकनीति' ऐसी प्रचलित धारणा बन गयी है जिसको हम सामान्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्यनीति, नई शिक्षा नीति, कृषि नीति या विदेश नीति के सदृश उल्लिखित करते हैं। यह ऐसे अन्तर्निहित क्षेत्रों से अन्तर्सम्बन्धित है जिसके जीवन का प्रभाव क्षेत्र निजी या विशुद्ध रूप से वैयक्तिक नहीं है, वरन् उभयनिष्ठ होता है।

मध्यप्रदेश में आदिवासी महिलाओं का अध्ययन और उदारीकरण का प्रभाव

दुर्गेश तेली

। kjkk% आदिवासी समुदाय या जनजातीय मुख्यतः जंगलों, पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। इनका व्यवसाय व आजीविका यहीं से संसाधनों के द्वारा चलती है और यहीं से अपनी आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं और अपना जीवनयापन करते हैं तथा जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करते हैं लेकिन देखा यह गया है कि इनकी यह स्थिति काफी दयनीय है हम उदारीकरण के संदर्भ में आदिवासी समुदाय की महिलाओं की स्थिति के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। मुख्यतः यह देखा जाता है कि इस समुदाय को शोषित ही माना जाता रहा है। हम सबसे पहले आदिवासी समुदाय की ऐतिहासिक स्थिति को संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न करेंगे तत्पश्चात् उदारीकरण के दौर में इनकी स्थिति को समझने के लिए उदारीकरण से पूर्व सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें कि सांस्कृतिक रीति-रिवाज, प्राकृतिक जुड़ाव, महिला संघर्ष तथा इनके व्यावसायिक संबंधी कार्य और स्थानांतरण जैसी समस्याओं पर विचार किया जाएगा। उदारीकरण से पूर्व की अवस्था को समझने के पश्चात् उदारीकरण के दौर में इस समुदाय पर होने वाले बदलावों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति की चर्चा करेंगे तत्पश्चात् इसके आर्थिक और सामाजिक बिन्दुओं के आधार पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में वहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा। इन सभी के आधार पर यह बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय और महिलाओं का भावनात्मक मूल्यों को ठेस पहुँचाया जा रहा है और इनके सोच और समझ पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है।

लोकनीति एवं नीति निर्मात्री संस्थाएँ

अम्बुजेश कुमार मिश्र

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य 'लोकनीति और नीति निर्मात्री संस्थाओं का सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत करना है। लोक नीतियाँ सरकार के सदृश ही प्राचीन हैं। अतीत में सरकार का स्वरूप जो भी रहा हो, जब और जहाँ जैसी भी सरकारें रही हैं, वहाँ लोक नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन हुआ है। जनता की विभिन्न माँगों और समस्याओं के समाधान के लिये सरकार जो नीतियाँ बनाती है उन्हें लोकनीति कहा जाता है। लोकनीति वह दिशा -निर्देश पत्र होता है जो सरकार के कार्यों तथा कार्यक्रमों को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। लोकनीति और लोक प्रशासन का घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा लोकनीति निर्माण लोक प्रशासन का सार है। लोकनीति का निर्धारण, निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं संशोधन का कार्य लोक प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। यद्यपि लोकनीतियाँ सरकारी निकायों द्वारा विकसित की जाती हैं, परन्तु गैर -सरकारी लोग और संस्थाएँ भी नीति निर्माण प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकती हैं। लोकनीति एक ऐसे ढाँचे का निर्धारण करती है जिसके अन्तर्गत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। अतः लोकनीति का निर्माण सरकार की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है क्योंकि यह संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती है। इनके निर्माण में जिन सरकारी गैर -सरकारी संरचनाओं का योगदान होता है उनमें प्रमुख रूप से प्राधिकारी गण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वृद्ध जन, सर्वोच्च प्रधान, प्रशासक, पार्षद, अधिपति और इसी प्रकार के अन्य लोग सम्मिलित हैं।

सुशासन और लोकनीति

महेश कुमार सिंह

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य 'सुशासन और लोकनीति' का विशद विश्लेषण प्रस्तुत करना है। सुशासन और लोकनीति वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विकास के निर्णायक एवं अनिवार्य घटक के रूप में विद्यमान है। ऐसे शासन का अभिप्राय सुशासन से होता है, जो जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरता हो, जिसमें कार्यकुशलता व प्रभावशीलता विद्यमान हो। सुशासन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध किसी भी शासन प्रणाली के स्वरूप से न होकर जनता को उपलब्ध कराये जाने वाली गुणवत्तायुक्त संसाधनों, सेवाओं व सुविधाओं से है, जिनका समुचित उपयोग करके जनता अपने सर्वतोन्नयन की ओर उन्मुख हो सके। सुशासन शासन का वह व्यावहारिक नियोजन है जिसमें शासन को आवश्यक रूप से अच्छा होना चाहिए, किन्तु इसके आदर्श एवं आनुभविक रूप से पालन बहुआयामी है। मानव अस्तित्व का शायद ही कोई पक्ष हो जो अच्छे व श्रेष्ठ शासन के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत शामिल न हो। मूल्यों की व्यक्तिपरक प्रकृति के कारण देश, काल तथा संस्कृति के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं। वर्तमान युग में 'ई-गवर्नेंस' सुशासन की ही नूतन विशिष्टता को संजोये हुए है। आधुनिक तकनीकी युग में इण्टरनेट (सोशल मीडिया) जनता और शासन के मध्य एक 'द्वार' की भूमिका में है जिसने दोनों के मध्य 'सम्पर्क-सुविधा' मुहैया कराई है।

विकासशील देशों में विकास प्रशासन की भूमिका

स्निग्धा त्रिपाठी

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य 'विकासशील देशों में विकास प्रशासन की भूमिका' का विशद विश्लेषण प्रस्तुत करना है। यद्यपि 'परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है तथापि मानव एक जिज्ञासु प्राणी होने के कारण सदैव विकास हेतु प्रयत्नशील रहा है। अतीत से वर्तमान तक का मानव इतिहास उसके सतत् विकास का ही द्योतक है, उसके प्रगति की नूतन कहानी है, उसके भविष्य का दिक्सूचक भी है। वस्तुतः परिवर्तन विकासात्मक होता है जिसके अभाव में विकास और विकास परिवर्तन बिना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में सतत् परिवर्तन एवं स्वयं की शक्ति तथा अस्तित्व को सुदृढ़ करते हुए विकास प्रगति पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में विकास सर्वाधिक प्रचलित विचारों में से एक है। इस सम्बन्ध में अमेरिकी विद्वान ब्रान ने यहाँ तक कह दिया कि, 'सारी दुनिया विकास से अभिशापित है, इससे बच पाना मुश्किल सा लगता है'।

प्रवासी भारतीय एवं भारत सरकार- संक्षिप्त अध्ययन

शीला कुमारी

I kjklk% प्रवासी भारतीय समुदाय विविध विजातीय और मिलनसार वैश्विक समुदाय है जो विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रवासी भारतीयों में भारतीय मूल के लोग और अप्रवासी भारतीय शामिल हैं जिन्हें भारत और इसके आंतरिक मूल्यों का विचार एक आम सूत्र में बाँधे हुए है। विश्व के प्रत्येक कोने में प्रवासी भारतीय समुदाय को कड़ी मेहनत, अनुशासन और हस्तक्षेप न करने और स्थानीय समुदाय के साथ सफलतापूर्वक तालमेल बनाए रखने के कारण जाना जाता है। प्रवासी भारतीयों ने अपने आवास के देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और स्वयं में ज्ञान एवं नवीनता का संचार किया है। ऐसे भारतीय मूल के लोगों को अपने पूर्वजों की भूमि, मिट्टी, गाँव, देश आदि से निरंतर लगाव बना हुआ है। इन सभी भारतीयों के अतिरिक्त विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय भी हैं जो उच्च शिक्षा के लिए वहाँ गए और वहीं बसकर वहाँ के नागरिक बन गए। ऐसे प्रवासी भारतीयों के साथ भारत का औपचारिक संबंध भारत के हित में है, क्योंकि भारत के पास वर्तमान में 25 मिलियन का एक सशक्त प्रवासी भारतीय समुदाय है। इस समुदाय के साथ संबंध बनाए रखना देश हित में है। यही कारण है कि प्रवासी आबादी के महत्व को देखते हुए इनके साथ एक सतत् और परस्पर लाभकारी संबंधता के लिए भारत सरकार द्वारा एक संस्थागत ढाँचा बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास की योजनाओं में भारत सरकार का योगदान : एक मूल्यांकन

मो. ताहिर अन्सारी

। kjk'k% भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसका सतत् संचालन गाँवों के द्वारा किया जाता है। जब तक गाँव समृद्ध नहीं होगा तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता है। गाँवों के विकास के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण विकास की योजनाओं में भारत सरकार के योगदान तथा मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल इण्डिया आदि योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इस शोध पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की समकालीन योजनाओं को विस्तृत ढंग से समझा जा सकता है।

औपनिवेशिक प्रशासन तथा बाढ़ नियंत्रण : उत्तर बिहार का विशेष सन्दर्भ

निशा कुमारी

I kjkak : उत्तर बिहार नदियों का क्षेत्र है। अनेकों नदियाँ उत्तर बिहार की भूमि पर बिछी हुई हैं जो गंगा की गोद को भरती हैं। साथ ही उत्तर बिहार विश्व के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित तथा पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ इस क्षेत्र में भारी बर्बादी का कारण बनती है। यद्यपि स्थानीय लोगों द्वारा अपने जीवन में नदी की संस्कृति के समावेशन की एक व्यापक तथा विकसित परंपरा देखने को मिलती है जिसमें वह नदी के बीच रहकर, इनके साथ समायोजन स्थापित करते आए परन्तु उनके पारंपरिक ज्ञान को पिछड़ा बताकर औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा व्यापक हस्तक्षेप किया गया। औपनिवेशिक प्रशासन की यह मान्यता थी कि नदियों के बहाव को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जिसके फलस्वरूप नदियों पर व्यापक रूप से तटबंधों तथा अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया। औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा यह प्रयास अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया जिसका स्थानीय जन-जीवन पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह लेख भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण के विभिन्न प्रयासों के वर्णन के माध्यम से पर्यावरण के औपनिवेशीकरण तथा विशेष रूप से नदियों के औपनिवेशीकरण का विश्लेषण करने का एक प्रयास है।

बांग्लादेश में इस्लामिक उग्रवाद का बदलता स्वरूप और उसकी चुनौतियाँ

रविन्द्र कुमार मीना

I kjka k%वर्तमान समय में बांग्लादेश इस्लामिक उग्रवाद के एक नए केन्द्र के रूप में उभरा है जिसका ज्वलंत उदाहरण ढाका में 1 जुलाई 2016 के आर्टिशन कैफे पर हुए हमले के रूप में देखा जा सकता है। जिसमें 20 से अधिक विदेशी नागरिक मारे गए थे। इस हमले की विशेषता यह रही कि इसने देश के इतिहास में पहली बार वैश्विक इस्लामिक उग्रवादी संगठन 'इस्लामिक स्टेट' तथा स्थानीय जेहादी संगठनों के व्यापक परिदृश्य को साफ-साफ परिलक्षित किया। मौजूदा दौर में इस्लामिक उग्रवादी संगठन अपना सीधा निशाना उदारवादी समूहों, ब्लार्गस एवं गैर-मुस्लिम समुदायों (अहमदिया) को प्रमुख रूप से बना रहे हैं। देश में समकालीन इस्लामिक उग्रवाद के इस स्वरूप को उभारने में वस्तुतः कई कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक घरेलू राजनीतिक दशा, विशेष इस्लामिक संस्कृति की उपज तथा वैश्विक परिदृश्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

भारत में निर्धनता की समस्या : चुनौतियाँ और समाधान

राजबीर सिंह दलाल एवं जगजीत सिंह

भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार इतना बढ़ गया है कि यह दुनिया में तीसरे स्थान पर आने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं दूसरी तरफ भारत की 60 फीसदी आबादी अभी भी भरपेट खाना नहीं खा पाती। आज भारत में आर्थिक विकास जितना बढ़ रहा है गरीबी भी उतनी ही बढ़ रही है। देश में गरीबी -उन्मूलन के लिए योजनाएं तो खूब बनाई गईं परन्तु इनका कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला है। वास्तव में अमीरी और गरीबी की विषमता घटने की बजाए बढ़ गई है। भारत में गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि हो रही है जो कि विकास में एक बाधा है तथा इसके अन्तः विरोधों को प्रदर्शित करती है। गरीबी एक बीमारी की तरह है जिससे अन्य समस्याओं जैसे अपराध, धीमा विकास, खराब सेहत, अशिक्षा आदि जुड़े हुए हैं।¹

THE INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
NON-ELECTED MEMBERS OF THE EXECUTIVE COUNCIL

President

M. VENKAIAH NAIDU
Vice-President of India

Chairman

T.N. CHATURVEDI
Former Governor of Karnataka

Vice President

SHEKHAR DUTT
(Former Governor of Chhattisgarh)

Co-opted Members

ARUN KUMAR GROVER
Vice-Chancellor
Panjab University,
Chandigarh-160014.

JOSEPH K. ALEXANDER
Chairman
IIPA Kerala Regional Branch,
T.C.14/2144, Medes Lane, Palayam,
Thiruvananthapuram-695034.

S.S. KSHATRIYA
Chairman
IIPA Maharashtra Regional Branch,
16th Floor, New Administrative Building,
Opp. Mantralaya, Hutatma Rajguru Chowk,
Madame Cama Road, Mumbai-400032.

N. LOKENDRA SINGH
Chairman
IIPA Manipur Regional Branch,
C/o Registrar,
Manipur University,
Canchipur,
Imphal-795003.

AJIT KUMAR TRIPATHI
Chairman
IIPA Odisha Regional Branch,

Secretaries to Government of India

AJAY MITTAL
Secretary
Department of Personnel & Training,
Ministry of Personnel,
Public Grievances & Pensions,
Govt. of India,
Room No.112,
North Block,
New Delhi-110001.

ASHOK LAVASA
Secretary
Department of Expenditure,
Ministry of Finance, Govt. of India,
Room No.128 C, North Block,
New Delhi-110001.

AMITABH KANT
Chief Executive Officer, NITI Aayog,
Govt. of India, NITI Bhavan,
Sansad Marg, New Delhi-110001.

IIPA Academic Staff

DOLLY ARORA
IIPA, New Delhi-110002.

K.K. PANDEY
IIPA, New Delhi-110002.

GIRISH KUMAR
IIPA,
New Delhi-110002.

Director & Member-Secretary
TISHYARAKSHIT CHATTERJEE
Indian Institute of Public Administration
I.P. Estate, Ring Road,
New Delhi-110002.

**INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
NEW DELHI**

INDIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION

(Quarterly: published since January 1955)

Editor: MAHENDRA PRASAD SINGH

Yearly Subscription:

Individuals: (Inland) Rs.425.00; (Abroad) \$120 or £48;

Single Copy: (Inland) Rs.120.00; (Abroad) \$30 or £12;

Special Number: (Inland) Rs.275.00; (Abroad) \$80 or £ 36

Institution/Library: (Inland) Rs. 700.00; (Abroad) \$ 240.00 or £ 96.00

Life Members of IIPA: Annual subscription: Rs.300.00; Single Copy Rs.75.00;

Special Number Rs.200.00

IIPANEWSLETTER

(Monthly recorder of national and international news of
public administration and allied matters since 1956)

Editor: TISHYARAKSHIT CHATTERJEE

Yearly Subscription: India: Rs. 10.00; Abroad: \$ 4.00 or £ 2.00

DOCUMENTATION IN PUBLIC ADMINISTRATION

(Quarterly: Published since 1973)

Editor: TISHYARAKSHIT CHATTERJEE, Director, IIPA, New Delhi

Assistant Editor: A.K. NATH, Dy. Librarian, IIPA, New Delhi

Yearly Subscription: India: Rs. 150.00; Abroad: \$ 60.00 or £ 24.00

NAGARLOK

(Urban Affairs Quarterly: Published since 1969)

Editor: TISHYARAKSHIT CHATTERJEE, Director, IIPA, New Delhi

Assistant Editor: V.N. ALOK, Associate Professor in Urban Finance,
IIPA, New Delhi

Yearly Subscription: India: Rs. 200.00.

लोक प्रशासन (अर्ध-वार्षिक)

सम्पादक: एस. एन. मिश्र

वार्षिक शुल्क : आजीवन सदस्य-रु. 150, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 200, संस्थागत ग्राहक-रु. 300

सामान्य अंक : आजीवन सदस्य-रु. 75, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 100, संस्थागत ग्राहक-रु. 150

विशेषांक : आजीवन सदस्य-रु. 100, व्यक्तिगत ग्राहक-रु. 200, संस्थागत ग्राहक-रु. 200

Bank drafts/postal orders should be drawn only in favour of
“**Director, Indian Institute of Public Administration**”

Note: Subscribers are advised to secure safe delivery
through Registered Post @ Rs. 100.00 per periodical.

For complete information about IIPA publications write to:

THE EDITOR

INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi-110 002 (India)